Implementation of Schemes in Madhya Pradesh

1834. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has formulated any plan to effectively implement various Centrally sponsored schemes in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the measures taken so far to made these schemes more useful?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (d) Centrally Sponsored Schemes (CSS) are formulated by the Central Ministries/Departments in consultation with the State Governments/UTs and are implemented by the States/UTs or their agencies. These schemes are monitored by various Central administrative Ministries concerned and Planning Commission's role is limited to generally reviewing the implementation of all Plan schemes including the CSS during the Annual Plan discussions. The Planning Commission in the above circumstances has not formulated any plan for effective implementation of various CSS in Madhya Pradesh.

विकास कार्यों में नियोजित श्रमिकों को आवश्यक वस्तुएं

1835. **श्री शिवचरण सिंह:**

श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 27 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1948 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों में नियोजित श्रमिकों को उनकी मजदूरी के एक भाग के रूप में उचित दर दुकानों के माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चला रही है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम में कार्यरत मजदूरों को आंशिक मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए खाद्यान्न आवंटित करती है। इन स्कीमों के तहत आंशिक मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों का वितरण करना राज्यों की इच्छा पर छोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इन रोजगार कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों के वितरण हेतु उचित दर दुकानों का इस्तेमाल कर रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई एक माडल स्कीम सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी। जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन योजना के तहत खाद्यान्नों के वितरण की रीति के विषय पर राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाता है।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता

1836. **श्री राम जेठमलानी:**

श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकास हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक सहायता से परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1995 में निर्माणधीन परियोजनाओं की मंत्रालय-वार संख्या कितनी-कितनी थी, और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता पहले ही स्वीकार कर ली गई थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Loss of FCI due to sale of Paddy

1837. SHRI ANANTRAM JAISWAL:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Food Corporation of India would be in double side loss by selling paddy as reported in 'Jansatta' dated 21st June, 1995;

(b) if so, the details thereof;